SJU Social Justice Union

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, मंगलवार 06 अगस्त 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक- 305

जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में धारा-144 लागू

» स्कूल-कॉलेज बंद

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर में जारी तनाव के बीच वहां कई जिलों में सीआरपीसी की धारा144 के तहत निषेधाज्ञा लगायी गई है. घाटी के कई जिलों में सोमवार को प्रतिबंध लगाते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई. सुरक्षा कारणों से जम्मू-कश्मीर में स्कूल और कॉलेज में कक्षाओं को निलंबित कर दिया गया है और परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं.

अधिकारियों ने बताया कि राजौरी और किश्तवाड़ जिलों तथा रामबाण जिले के बनिहाल इलाके में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है. वहीं जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में निषेधाज्ञा लागू की गई है. उन्होंने बताया कि सरकार ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत श्रीनगर जिले में एहतियाती तौर पर रविवार देर रात प्रतिबंध लगाए.

प्रशासन की तरफ से जारी आदेशा के अनुसार, लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध है और शिक्षण संस्थान (श्रीनगर जिल में) भी बंद रहेंगे. इस आदेश में कहा गया कि सार्वजनिक बैठक करने या रैली निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध है. आवश्यक सेवाओं के अधिकारियों के पहचान पत्र उनकी आवाजाही के पास के रूप में मान्य होंगे.

जम्मू, किश्तवाड़, रिआसी, डोसा और उधमपुर जिले में स्कूलों और कॉलेजों को सोमवार को बंद रखने का आदेश दिया गया है. वहीं किश्तवाड़ के उपायुक्त अंग्रेज सिंह राणा ने कहा, किश्तवाड़ में एहतियाती तौर पर हमने आज रात से सिर्फ रात के लिए कर्फ्यू लगाया गया है. उन्होंने बताया कि जिले में स्कूल और कॉलेज बंद हैं.

अधिकारियों ने बताया कि राजौरी जिले में भी रविवार रात से कर्फ्यू लगाया गया और वहां भी सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने का आदेश दिया गया है. बनिहाल में स्पीकर लगे वाहनों से रात को कर्फ्यू लगने की घोषणा की गई. उन्होंने बताया कि जम्मू विश्वविद्यालय भी सोमवार को बंद रहेगा और सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं.

'मैंने पहले ही आगाह किया था'

» कश्मीर पर बोले चिदंबरम

नईदिल्ली(आरएनएस)। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने जम्मू-कश्मीर में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं की नजरबंदी की आलोचना करते हुए सोमवार को कहा कि उन्होंने राज्य में कोई अनुचित कदम उठाये जाने के प्रति पहले ही आगाह किया था।

चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, मैंने जम्मू-कश्मीर में कोई अनुचित कदम उठाये जाने के प्रति पहले ही आगाह किया था। ऐसा लगता है कि सरकार बड़ा कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज का दिन बीतने से पहले हमें पता चल जायेगा कि क्या जम्मू-कश्मीर में कोई बड़ा संकट आने वाला है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के नेताओं की नजरबंदी इस बात का संकेत है कि सरकार अपना मकसद पूरा करने के लिए सभी लोकतांत्रिक नियमों और सिद्धांतों का उल्लंघन करेगी। उन्होंने कहा, मैं नजरबंदी की निंदा करता हूं। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। सरकार ने वहां 25 हजार से अधिक अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। गत शुक्रवार से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गयी है तथा राज्य में गये पर्यटकों को वापस लौटने को कहा गया है। लोगों को घरों से न निकलने को कहा गया है।

महत्वपूर्ण एवं खास

काहिरा में कारों की भिड़ंत से भीषण विस्फोट, 19 लोगों की मौत, 30 घायल

काहिरा (आरएनएस)। मिस्त्र के काहिरा में देर रात कई कारों की भिड़ंत और उसके बाद हुए भीषण विस्फोट के कारण कम से कम 19 लोगों की मौत हो गयी और 30 अन्य घायल हो गए। मिस्त्र के स्वास्थ मंत्रालय ने बयान जारी कर यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि गलत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने पेशनल ट्यूमर सेंटर के पास सामने से आ रही तीन कारों को टक्कर मार दी जिसके कारण विस्फोट हो गया। हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गये। मिस्त्र के स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि अधिकारी अन्य शवों की तलाश कर रहे हैं जो शायद नील नदी में गिर गए होंगे, जो अस्पताल के बगल में स्थित है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विस्फोट के कारण कारों में आग लग गयी और उसकी लपटें काफी दूर तक नजर आ रही थी। मंत्रालय ने बताया कि घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। मिस्त्र के सरकारी अभियोजक घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं।

अल पासो गोलीबारी में मारे गए 20 लोगों में से 6 मेक्सिकन नागरिक

मेक्सिको सिटी (आरएनएस)। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस एंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रादोर ने रविवार को कहा कि अमेरिका के अल पासो शहर में हुई गोलीबारी में मारे गए 20 लोगों में से छह मेक्सिको के नागरिक थे। गोलीबारी की घटना के एक दिन बाद मिकोआकैन शहर में एक कार्यक्रम के दौरान ओब्रादोर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्यवश इसकी पुष्टि हो गई है कि मृतकों में 6 मेक्सिको के नागरिक थे।' वहीं दूसरी ओर वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्टपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में घृणा के लिए कोई जगह नहीं है। हिंसा के लिए मानसिक बीमारियों को दोषी ठहराते हुए ट्रंप ने रविवार को कहा, 'हमारे देश में घृणा के लिए कोई जगह नहीं है। न्यू जर्सी में ट्रंप ने कहा, 'हमें इसे रोकना होगा। हमोर देश में यह वर्षो से चल रहा है... ।' बता दें कि अमेरिका में दो जगह पर हुई गोलीबारी में 29 लोग मारे गए हैं।

पुलिस कर्मी ने साथियों पर बरसाई गोलियां, सात की मौत

काबुल (आरएनएस)। देश के दक्षिणी प्रांत कंधार में एक पुलिस कर्मी ने अपने सहकर्मियों पर गोलियां चलाई, जिसमें सात पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अफगान पुलिसकर्मियों या सैनिकों के अपने हथियारों का इस्तेमाल कर अफगान बलों या अंतरराष्ट्रीय सैनिकों पर हमला करने की यह ताजा घटना है। प्रांतीय प्रवक्ता जमाल नासेर बारेकजाई ने कहा कि शाह वली कोट जिले में गोलीबारी कर हमलावर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। इस बीच, तालिबान के प्रवक्ता कारी युसूफ अहमदी ने कहा कि हमलावर ने तालिबान का हाथ थाम लिया है। तालिबान ने देश में अपने हमले बढ़ा दिए हैं।

मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू-कश्मीर पर चर्चा

नईदिल्ली(आरएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सोमवार सुबह यहां हुई बैठक में जम्मू-कश्मीर के संबंध में चर्चा की गयी। समझा जाता है कि बैठक में वहां के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में हुए विचार-विमर्श के बारे में तुरंत आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पायी है। बताया गया है कि संसद सत्र के कारण गृह मंत्री अमित शाह पहले संसद में ही इस संबंध में बयान देंगे।

जेएनयू की छात्रा से रेप, बेसुध हालत में मिली पीड़िता

नईदिल्ली। दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) की छात्रा से रेप का मामला सामने आया है. मिली जानकारी के मुताबिक, मंदिर मार्ग इलाके में पीड़िता बेसुध हालत में मिली थी. दो दिन पहले हुई इस घटना में रविवार को मंदिर मार्ग थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित जेएनयू स्टूडेंट मंदिर मार्ग इलाके से जेएनयू जाने के लिए कैब बुक की थी. इसी दौरान कैब ड्राइवर ने छात्रा के साथ रेप कर दिया. ड्राइवर फिलहाल फरार बताया जा रहा है. पुलिस लड़की के बयान और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश में जुट गई है.

पीड़ित जेएनयू स्टूडेंट ने बताया कि ड्राइवर ने नशीला पदार्थ खिलाकर कैब में ही उसके साथ रेप किया. इसके बाद पीड़िता को आईआईटी के पास एक पार्क में छोड़ दिया. जब शनिवार सुबह लोग पार्क में टहलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने पीड़ित को बेसुध हालत में पाया. इसके बाद उसे तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले गए. लड़की की आईडी कार्ड से उसकी पहचान हो पाई.

आयकर विभाग को लेकर राहुल ने सीतारमण पर साधा निशाना

नईदिल्ली। कैफे कॉफी डे (सीसीडी) के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ की कथित खुदकुशी एवं कुछ बड़े उद्योगपतियों की ओर से अर्थव्यवस्था की स्थिति पर दिए बयानों की पृष्ठभूमि में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि आयकर विभाग सरकारी राजस्व में कमी की भरपाई के मकसद से लोगों के पीछे पड़ा हुआ है.

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि हाथी को सिर्फ दो पाउंड चावल लेना चाहिए और उसे धान के पूरे खेत को नष्ट नहीं करना चाहिए. इस बीच, आयकर विभाग रूपी हाथी भारत के राजस्व में गिरावट की भरपाई के लिए मतवाला बनकर दौड़ रहा है.

पिछले दिनों खुदकुशी करने वाले वीजी सिद्धार्थ ने कथित तौर पर सुसाइड नोट लिखा था. जिसमें उन्होंने आयकर विभाग की ओर से किये जा रहे कथित उत्पीड़न का उल्लेख किया था. इस नोट की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई.

दूसरी तरफ, राहुल बाजाज और किरण मजूमदार जैसे कई उद्योगपतियों ने अर्थव्यवस्था की स्थिति और आयकर विभाग को लेकर बयान दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया उन्नाव रेप पीड़िता को इलाज के लिए शिफ्ट करने का आदेश

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल उन्नाव रेप पीड़िता को एयरलिफ्ट कर दिल्ली के एम्स लाने का आदेश दिया है. उन्नाव केस की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने सोमवार को यह आदेश दिया.

ज्ञात हो कि उन्नाव रेप पीड़िता का इलाज लखनऊ के ट्रामा सेंटर में चल रहा है. पीड़िता की हालात अभी नाजुक बनी हुई है और वह हादसे के बाद से ही वेंटीलेटर पर है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीड़िता के परिजन और केजीएमयू से दिल्ली एयरलिफ्ट करने के संबंध में जानकारी मांगी थी, जिसका जवाब देते हुए सीबीआई ने कहा था कि पीड़िता का परिवार लखनऊ में हो रहे इलाज से सतुष्ट है. जबकि केजीएमयू का कहना था कि अगर परिजन चाहें तो वे कहीं और लेकर जा सकते हैं.

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एयरलिफ्ट करने की मांग की थी. मालीवाल का कहना था कि पीड़िता की हालत काफी नाजुक है. उसे दिल्ली एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज की जरूरत है. उन्होंने कहा था कि अगर पीड़िता को दिल्ली लाया जाता है तो उसके इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी.

उधर केजीएमयू ने सोमवार को पीड़िता का मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि दोनों मरीजों (पीड़िता व उसके वकील) की हालत नाजुक, लेकिन स्थिर बनी हुई है. केजीएमयू के मुताबिक महिला मरीज (पीड़िता) की हालत में सुधार हुआ है. महिला मरीज अब कमांड फॉलो कर रही हैं. महिला मरीज एक आंख खोलकर बातों को समझ रही है. बुखार आने की प्रवृत्ति कम हुई है।

कर्नाटक में बाढ़ की स्थिति गंभीर, कृष्णा नदी उफान पर

बेलगावी। कर्नाटक में पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के जलाशयों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से कृष्णा नदी के उफान पर होने के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने उत्तरी कर्नाटक के सभी बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बाढ़ का पानी स्कूल भवनों में घुस गया है और सड़कों पर घुटने से ऊपर तक पानी भरा हुआ है लिहाजा स्कूलों में तीन दिन के लिए अवकाश की घोषणा कर दी गयी है।

मुख्यमंत्री ने बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित बेलगावी, बगलकोट, रायचूर, बीजापुर और याडगीर जिलों में स्थिति का जायजा लेने के बाद कहा कि सेना की मदद मांगी है और सेना के जवान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, अग्निशमन विभाग की टीम के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्य चला रहे हैं। बाढ़ में फंसाने लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए दिन-रात काम चल रहा है।

कृष्णा नदी के किनारे के बाढ़ प्रभावित गांवों से लगभग 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मलाप्रभा और घटाप्रभा जलाशयों में पानी का भारी प्रवाह जारी है। तीन हजार हेक्टेयर में खड़ी फसल बाढ़ से डूब गयी।

370 नहीं होता तो 41 हजार लोग नहीं मारे गए होते- अमित शाह

नई दिल्ली। 370 विपक्ष के हंगामे के बीच राज्य सभा में गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के लिए सोमवार को ऐतिहासिक बदलाव की पेशकश की। उन्होंने यहां से अनुच्छेद 370 व 35(ए) हटाने की सिफारिश की। इसके अनुसार, जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में मंगलवार को पेश किया जाएगा। वहीं लोकसभा में आज ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 पारित कराया गया। राष्ट्रपति शासन के बाद वहां चुनाव हुए और आज 40 हजार पंच-सरपंच वहां के विकास में योगदान दे रहे हैं। 40 हजार पंच-सरपंच का अधिकार 70 साल तक जम्मू कश्मीर के लोगों से ले लिया। इसका जिम्मेदार है अनुच्छेद 370 था- अमित शाह

आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र प्रफुल्लित नहीं हुआ। आर्टिकल 370 और 35 के कारण भ्रष्टाचार फला-फूला, पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा। आर्टिकल 370 और 35 के कारण ही गरीबी घर कर गई- अमित शाह आर्टिकल 370 अस्थाई था और इसे कभी न कभी हटना था, लेकिन पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए इसे हटाने की हिम्मत नहीं की। कैबिनेट ने आज हिम्मत दिखाकर और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए यह फैसला लिया है- अमित शाह मैं आज सदन के सामने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ हूं।

370 व 35 खत्म करने की केंद्र सरकार ने बताई ये बड़ी वजह

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने को लेकर तमाम दलों और जानकारों की अलग-अलग राय है। ज्यादातर लोग केंद्र के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं कुछ विपक्षी दल और अन्य लोग इस फैसले के विरोध में हैं। मालूम हो कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के साथ ही 35ए भी स्वतः खत्म हो गई है। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे अब केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि तमाम विरोधों के बावजूद क्यों उसके लिए ये फैसला लेना इतना जरूरी था। न्यूज एजेंसी द्धहस्र के अनुसार केंद्र सरकार ने इस बड़े फैसले पर अपना रुख स्पष्ट किया है। संसद में अनुच्छेद-370 व 35ए खत्म करने पर केंद्र सरकार ने अंग्रेजी की एक कहावत कही है, 370 मतलब अनुच्छेद-370 कमरे में बंद हाथी की तरह है। सभी इससे परेशान हैं। सब इसे हटाना भी चाहते हैं, लेकिन सामना कोई नहीं करना चाहता।

आतंकवाद का होगा खात्मा

केंद्र सरकार ने कहा कि अनुच्छेद-370 को हटाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसकी वजह से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पनप रहा था। इसकी वजह से राज्य में भ्रष्टाचार बेकाबू हो चुका था। इसकी वजह से राज्य का विकास बाधित हो रहा था। वहां बाहरी निवेश नहीं हो पा रहा था। सरकार ने जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती द्वारा संविदान के अनुच्छेद-370 को निरस्त किए जाने के विरोध को भी नजरअंदाज कर दिया है।